सेक्रेटरी, यूपीएससी और अन्य

बनाम

एस. कृष्णा चैतन्य

सिविल अपील नंबर 6349/2011

5 अगस्त, 2011

शिक्षा/शैक्षणिक संस्था-सिविल सर्विस परीक्षा- प्रतिवादी उम्मीदवार की दलील कि कोरियर के माध्यम से उसे सिविल सर्विस परीक्षा का प्रवेश पत्र प्राप्त नहीं हुआ-संस्था द्वारा जारी मोहर लगी हुई पावती कार्ड जो प्रतिवादी को जारी किया गया था उसे पेश नहीं किया-माननीय उच्च न्यायालय ने अंतरिम आदेश पारित कर परीक्षार्थी को परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति दी- यह अपील में निर्धारित किया गया कि परीक्षार्थी आवेदन पत्र भेजने का कोई सबूत पेश नहीं कर सका-इसलिये अपीलार्थीगण को यह निर्देश नहीं दिया जा सकता कि प्रत्यर्थी का अंतिम परिणाम निकाला जाये क्योंकि जब उसका आवेदन पत्र ही अपीलार्थीगण द्वारा विहित समयावधि के भीतर प्राप्त नहीं किया गया-परीक्षार्थी के प्रारम्भिक परीक्षा में भाग लेने के अलावा उसके अंतिम मुख्य परीक्षा में भी भाग ले लिया और इस अंतरिम आदेश की आड़ में वह साक्षात्कार के लिये भी उपस्थित हो गया जबकि उसे ऐसा अंतरिम आदेश ऐसे अधिकार प्रदान नहीं करता है-इस तरह के अंतरिम आदेश न्यायालय को देने से बचना चाहिये क्योंकि ऐसे

आदेश से इस तरह की संस्थाओं को परीक्षा लेने का कार्यभार बढता है तथा इसके साथ जो लोग अदालत से ऐसे आदेश प्राप्त करने के लिये आवेदन करते हैं उन्हें झूठी दिलासा दिलाता है-यधपि आजकल अदालतें इस तरह के छात्रो के पक्ष में अंतरिम आदेश देकर उनके साथ सहानूभूति का व्यवहार अपनाते हुये संस्थान को ऐसे छात्रों को परीक्षा में भाग लेने के लिये निर्देशित करते हैं जो परीक्षा में भाग लेने योग्य है या नहीं- अपवादिक मामलों में विशेष कारण अंकित करते हुये अगर न्यायालय ऐसा निर्देश देता है तो ऐसे मामलों का परिणाम आने से पूर्व गुणावगुण पर मामले का निस्तारण कर देना चाहिये।

अंतरिम आदेश की व्यापकता के बारे में यह निर्धारित किया गया कि अंतरिम आदेश इस तरह के नहीं होने चाहिये जो याचिका या आवेदन को अंतरिम स्टेज पर ही उसका अंतिम रूप से निस्तारण कर देता हो-आम तौर पर मामला जब अंतरिम चरण पर होता है तो जो राहत मामले के निपटारे के समय दी जाती है उसे अंतरिम चरण पर नहीं दिया जा सकता।

प्रत्यर्थी का यह मामला था कि उसने यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा 2010 देने के लिये उसने डीटीडीसी कोरियर कम्पनी के माध्यम से आवेदन भेजा था जो उसने दिनांक 28 जनवरी 2010 को भेजा था। कोरियर कम्पनी ने प्रत्यर्थी को यह सूचना दे दी कि उन्होंने यूपीएससी को 29 जनवरी 2010 को आवेदन पत्र की डिलीवरी कर दी। इस पर दिनांक

20-04-2010 को प्रत्यर्थी ने यूपीएससी को एक अभ्यावेदन पत्र दिया कि उसे परीक्षा में बैठने का प्रवेश प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। जिस पर अपीलाण्ट यूपीएससी संस्था ने प्रत्यर्थी को सूचित किया कि आपका आवेदन उन्हें प्राप्त नहीं हुआ हैA अगर आपने आवेदन भेजा है तो उसके सबूत में यूपीएससी द्वारा विधिवत मोहर लगा हुआ पावती कार्ड प्रस्तुत करे ताकि आपके मामले में आगे कार्यवाही कर सके कि प्रत्यर्थी को अपीलाण्ट द्वारा जारी किया गया कोई पावर्ती प्राप्त नहीं हुआ है। इस पर प्रत्यर्थी ने मूल आवेदन पत्र केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के समक्ष पेश किया।

अंतरिम आदेश के जरिये अधिकरण ने प्रत्यर्थी से आवेदन फार्म की प्रति जो उसने अपीलार्थीगण को भेजी थी उसे पेश करने का निर्देश दिया गया और साथ में ही अधिकरण ने अपीलार्थीगण को भी निर्देश दिया कि आप प्रत्यर्थी को प्रारम्भिक परीक्षा में बैठने हेतु प्रवेश पत्र जारी करे तथा यह प्रवेश परीक्षा के अंतिम परिणाम के अधीन होगा। दोनों पक्षकारान ने इस अंतरिम आदेश की पालना की।

प्रत्यर्थी का मूल आवेदन अंततः स्वीकार हो गया। अपीलार्थीगण को निर्देश दिया गया कि आप अंतिम परिणाम निकालें। अपीलार्थीगण ने अधिकरण के इस आदेश के विरूद्व माननीय उच्च न्यायालय में अपील प्रस्तुत की। माननीय उच्च न्यायालय ने याचिका को निस्तारित करते हुये

यह आदेश दिया कि प्रत्यर्थी को सिविल सर्विस की मुख्य परीक्षा में बैठने की ईजाजत दी जाये तथा यदि वह मुख्य परीक्षा पास कर लेता है तो साथ में साक्षात्कार में भी उपस्थित होने की अनुमति दी जाये। इस मामले के लम्बन के दौरान प्रत्यर्थी ने परीक्षा में भाग लिया और मौखिक साक्षात्कार में उपस्थित हुआ। अपीलाण्टस द्वारा प्रत्यर्थी का परीक्षा परिणाम बंद लिफाफे में रखते हुये उसे घोषित नहीं किया गया।

यह वर्तमान अपील माननीय उच्च न्यायालय के इस आदेश को चुनौती देते हुये तत्काल अपील दायर की गई। प्रत्यर्थी ने इस अंतरिम प्रार्थना पत्र को यह निवेदन करते हुये पेश किया कि अपीलार्थीगण को परिणाम घोषित करने एवं विशेष कैडर में एक पद खाली रखने के लिये निर्देश दिये जावे ताकि अंतरिम आवेदन जो दायर किया गया है उसकी पालना में वह सेवा में ज्वाईन कर सके।

1.1 माननीय उच्च न्यायालय ने अपील को स्वीकार करते हुये यह निर्धारित किया कि अधिकरण के समक्ष प्रत्यर्थी ने अपनी याचिका के समर्थन में कोई साक्ष्य पेश नहीं की जो यह साबित कर सके कि प्रत्यर्थी का आवेदन पत्र अपीलाण्ट संस्थान को प्राप्त हुआ है। शुरूआत से ही यानि जिस चरण में ट्रिब्यूनल के समक्ष प्रत्यर्थी द्वारा मूल आवेदन पत्र पेश किया गया था। उसमें प्रत्यर्थी ने डीटीडीसी कोरियर एंड कम्पनी के रीजनल मैनेजर के शपथ पत्र पर भरोसा करते हुये यह प्रार्थना पत्र पेश

किया था। शपथ पत्र में कोरियर कम्पनी द्वारा यह बताया गया कि प्रत्यर्थी का आवेदन पत्र अपीलार्थीगण के यहां दिनांक 29-10-2010 को सौप दिया गया था। उक्त आवेदन पत्र को प्रत्यर्थी द्वारा व्यक्तिगत रूप से यूपीएससी में जमा नहीं करवाया गया था बल्कि इसे कोरियर एजेंसी के कर्मचारी द्वारा संस्थान के यहां जमा करवाया गया था। उक्त कथन को साबित करने के लिये कोरियर कम्पनी की डिलीवरी रन शीट दिनांक 29-10-2010 की पेश की गई। यह रन शीट रिकार्ड का भाग है। जिसका अवलोकन करने पर यह कहीं भी साबित नहीं होता है कि संस्थान या इसके कर्मचारी द्वारा प्रत्यर्थी के आवेदन पत्र प्राप्त करने की कोई पावती दी गई हो। उक्त रन शीट में बहुत तरह के कंसाईनमेंट का यूपीएससी को संदर्भित करते हुये हवाला है जिसमें पांच अलग नामों के कंसाईनमेंट का हवाला दिया गया है लेकिन प्रत्यर्थी का कोई आवेदन जो यूपीएससी द्वारा इस कोरियर कम्पनी के जरिये प्राप्त किया गया हो,इसका कोई हवाला नहीं है। इसलिये कोरियर कम्पनी द्वारा जो रिकार्ड पेश किया गया है, उससे यह नहीं कहा जा सकता कि प्रत्यर्थी का परीक्षा में बैठने का आवेदन पत्र यूपीएससी द्वारा स्वीकार कर लिया गया है।

1.2 हस्तगत मामला एक नौजवान व्यक्ति के भविष्य के इर्द गिर्द घुमता है जिसका सिविल सर्वेन्ट के रूप में चयन हो सकता था। जिस सिस्टम के जरिये अपीलकर्ताओं द्वारा जो आवेदन प्राप्त करने की प्रणाली

अपनाई गई है वह व्यापक और दोषरहित है। यदि प्रतिवादी का आवेदन पत्र अपीलाण्टस को दिये गये तरीके से प्राप्त हुआ होता तो इसे कहीं दर्ज किया गया होता। यहां तक कि प्रतिवादी के आवेदन पत्र का 8 अंकों का नम्बर भी कहीं दर्ज नहीं किया गया है। कोरियर कम्पनी के आवेदन पत्र के प्राप्ति को अपीलांट कर्ता द्वारा हाथ से डिलीवरी माना गया है। हाथ से आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में मौके पर ही एक विशेष संख्या नम्बर का चिन्ह जारी कर एक पावती कार्ड उस व्यक्ति को सौंप दिया जाता है जो आवेदन पत्र वितरित करता है। यदि आवेदन पत्र कोरियर एजेंसी के किसी प्रतिनिधि द्वारा अपीलकर्ताओं के कार्यालय में पहुंच गया होता तो अपीलकर्ता के पास एक अलग संख्यात्मक चिन्ह वाली विधिवत मुद्रांकित पावती कार्ड न देने का कोई कारण नहीं था। इस प्रकार प्रत्यर्थी द्वारा कोई सबूत प्रस्तुत नहीं किया गया कि उसके द्वारा भेजा गया आवेदन पत्र अपीलांटकर्तागण को प्राप्त हो गया।

1.3 अंतरिम आदेश पारित करते समय ट्रिब्यूनल को भी यह निश्चित नहीं था कि प्रत्यर्थी द्वारा भेजा गया आवेदन पत्र अपीलकर्ता को प्राप्त हुआ या नहीं। इस प्रकार प्रत्यर्थी को सिविल सेवा परीक्षा देने की अनुमति देने के संबंध में अपीलकर्ताओं को अंतिम निर्देश देते समय भी, ट्रिब्यूनल एक निश्चित निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा कि प्रत्यर्थी का आवेदन पत्र अपीलाण्ट को प्राप्त हुआ या वह कहीं अपीलाण्टस द्वारा गुम कर दिया

गया। ऐसी परिस्थितियों में अपीलकर्ताओं को प्रत्यर्थी को परीक्षा देने की अनुमति देने का निर्देश देना उचित नहीं था विशेषकर जब रिकार्ड पर दिखाने के लिये प्रत्यर्थी के पास कोई सबूत नहीं था कि उसने आवेदन पत्र जमा करवा दिया है।

1.4 प्रत्यर्थी के अनुसार- उसने 28 जनवरी 2010 को बताये गये कोरियर के माध्यम से अपना आवेदन पत्र अग्रेषित किया था। यदि प्रत्यर्थी को अपना आवेदन पत्र अग्रेषित करने की तारीख से 30 दिनों की अवधि के लिये कोई पावती नहीं मिली तो उसे अपीलार्थीगण के कार्यालय में आवश्यक पूछताछ करनी चाहिये थी कि उसे आवेदन पत्र जमा करवाने की पावती अपीलार्थीगण से नहीं मिली है। जैसाकि विज्ञापन में यह बताया गया है कि एक विवेकपूर्ण उम्मीदवार के रूप में प्रत्यर्थी को फरवरी 2010 के अंत तक पूछताछ करना चाहिये थी लेकिन प्रत्यर्थी को इन तथ्यों की जानकारी थी फिर भी उसने 20 अप्रेल 2010 तक इंतजार किया तथा ऐसी कोई अपीलार्थीगण के कार्यालय में पूछताछ नहीं की कि उसका आवेदन पत्र उनके कार्यालय में प्राप्त हुआ है या नहीं। राज्य का सजग अधिकारी बनने के इच्छुक छात्र को अपने आवेदन के प्रति इतना उदासीन होने की उम्मीद नहीं की जा सकती कि वह इस तरह की परीक्षा देने के मामले में दो महिने तक इंतजार करे जबकि यहां यह उल्लेख करना समीचीन होगा कि प्रत्यर्थी ने पहले भी परीक्षा दी थी और दुर्भाग्यवश वह

पूर्व परीक्षा में पास नहीं हो सका। इस प्रकार प्रत्यर्थी को इस बात का अनुभव था कि आवेदन पत्र इस परीक्षा में बैठने हेतु कैसे भरा जाता है उसे कैसे जमा किया जाता है और अपीलार्थीगण द्वारा कैसे आवेदन प्राप्त होने पर पावती कार्ड जारी किया जाता है। इस लापवाही के कारण प्रत्यर्थी स्वयं को कष्ट सहना पड़ा जिसके लिये वह स्वयं दोषी है। उसके लिये अपीलार्थीगण को प्रत्यर्थी का अंतिम परिणाम जारी करने के लिये निर्देशित नहीं किया जा सकता- विशेषतः जब विहित समयावधि के भीतर प्रत्यर्थी द्वारा पेश किया गया आवेदन पत्र अपीलार्थीगण को प्राप्त ही नहीं हुआ। अतः ट्रिब्यूनल के अंतरिम आदेश की अनुपालना में प्रत्यर्थी द्वारा पेश किये गये दुसरे आवेदन पत्र को विचार में नहीं लिया जा सकता है।

2. **एक अंतरिम आदेश** की ऐसी प्रकृति नहीं होनी चाहिये जिसके आधार पर किसी याचिका/आवेदन जैसा भी मामला हो उसको अंतिरम चरण पर अंतिम रूप से निस्तारित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। हालांकि अक्सर अदालतें छात्रों के प्रति अधिक सहानूभूति रखती है और अंतरिम आदेशों द्वारा अधिकारियों को यह बिना सुनिश्चित किये कि संबंधित उम्मीदवार को परीक्षा देने का अधिकार है या नहीं। फिर भी परीक्षा में बैठने की अनुमति के निर्देश दिये जाते हैं। जबकि ऐसा किसी असाधारण मामले में किसी विशेष कारण से, यह निर्देश दिया जा सकता है तो अदालत को परिणाम घोषित होने से पहले मामले को गुणावगुण के

आधार पर अंतिम रूप से निपटाना चाहिये। हस्तगत मामले में प्रत्यर्थी ने न केवल प्रारम्भिक परीक्षा दी बल्कि मुख्य परीक्षा भी दी और अंतरिम आदेश के आधार पर वह साक्षात्कार के लिये भी उपस्थित हो गया। जबकि उसे किसी भी परीक्षा में भाग लेने का अधिकार नहीं था। इसलिये ऐसा अंतरिम आदेश देने से अदालतों को बचना चाहिये क्योंकि ऐसे लोग न केवल परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था का काम बढाते है बल्कि अदालत जाने वाले अभ्यार्थियों को झूठी उम्मीद देते हैं।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 6349/2011।

उच्च न्यायालय आंध्रप्रदेश, हैदराबाद के सिविल रिट पीटीशन नं-33367 के विरूद्व अपील में निर्णय व आदेश दिनांकित 07-02-2011 से उत्पन्न।

अंतर्वर्ती आवेदन संख्या 1

निर्णय

1- अनुमति दी गई।

2. हैदराबाद में आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय द्वारा 2010 के WP संख्या 33367 में पारित दिनांक 7.2.2001 के निर्णय और आदेश से व्यथित होकर, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, हैदराबाद पीठ द्वारा पारित 1 सितंबर, 2010 के आदेश की पुष्टि की गई। यह अपील

अपीलकर्ताओं- संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) के सचिव और संयुक्त सचिव द्वारा दायर की गई है।

3. प्रतिवादी के मामले के अनुसार, सिविल सेवा परीक्षा, 2010 देने की इच्छा रखते हुए, उसने अपना आवेदन पत्र भरा था और उसे डीटीडीसी कूरियर एंड कार्गो लिमिटेड के माध्यम से यूपीएससी को भेजा था। प्रतिवादी ने अपना आवेदन पत्र को सौंप दिया था और कूरियर ने प्रतिवादी को सूचित किया था कि आवेदन पत्र 29 जनवरी, 2010 को यूपीएससी को वितरित किया गया था। इस प्रकार, प्रतिवादी के अनुसार, उसका आवेदन पत्र यूपीएससी द्वारा विधिवत प्राप्त किया गया था और, इसलिए, वह अपने प्रवेश प्रमाण पत्र की उम्मीद कर रहा था, लेकिन चूंकि उसे अप्रैल, 2010 के महीने में भी यह प्राप्त नहीं हुआ था, इसलिए उसने 20 अप्रैल, 2010 को अपीलकर्ताओं को एक अभ्यावेदन दिया था, जिसमें उस प्रवेश प्रमाण पत्र जारी न होने के संबंध में शिकायत की गई थी। प्रतिवादी द्वारा दिए गए पूर्वोक्त अभ्यावेदन के अनुसरण में, 23 अप्रैल, 2010 को एक पत्र प्रतिवादी को संबोधित किया गया था, जिसमें उसे सूचित किया गया था कि सिविल सेवा परीक्षा (प्रारंभिक), 2010 के लिए उसका आवेदन अपीलकर्ताओं को प्राप्त नहीं हुआ था। अपीलकर्ताओं को मामले में आगे की कार्रवाई करने में सक्षम बनाने के लिए यूपीएससी द्वारा विधिवत मुहर लगी पावती कार्ड प्रस्तुत करने का भी अनुरोध प्रत्यर्थी से किया गया था

4. चूंकि प्रतिवादी को अपीलकर्ताओं से कोई पावती कार्ड नहीं मिला था, इसलिए प्रतिवादी ने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, हैदराबाद में 2010 अपील संख्या 470 दायर करके अंतरिम राहत के लिए प्रार्थना की, ताकि अपीलकर्ताओं को निर्देशित किया जा सके। प्रतिवादी को एक प्रवेश प्रमाणपत्र जारी करें ताकि प्रतिवादी परीक्षा दे सके। 12 मई, 2010 के एक अंतरिम आदेश द्वारा, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण ने प्रतिवादी को अपने आवेदन पत्र की एक प्रति अपीलकर्ताओं को जमा करने का निर्देश दिया और अपीलकर्ताओं ने प्रतिवादी को एक प्रवेश प्रमाण पत्र जारी करने का निर्देश दिया ताकि प्रतिवादी परीक्षा दे सके। यह स्पष्ट किया गया कि प्रवेश प्रमाणपत्र उक्त मूल आवेदन के अंतिम परिणाम के अधीन होगा।

5. केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) द्वारा पारित पूर्वोक्त अंतरिम आदेश के अनुसरण में, प्रतिवादी ने एक और आवेदन पत्र दाखिल किया था जो अपीलकर्ताओं को 17 मई, 2010 के आसपास प्राप्त हुआ था और उक्त आवेदन पत्र के अनुसरण में, एक प्रवेश प्रमाण पत्र अपीलकर्ताओं द्वारा प्रतिवादी को जारी किया गया और उसने सिविल सेवा परीक्षा (प्रारंभिक) में भाग लिया।

6. उपरोक्त मूल आवेदन पर अंततः कैट द्वारा सुनवाई की गई और 1 सितंबर, 2010 के एक आदेश द्वारा आवेदन की स्वीकृति दी गई, जिसके तहत अपीलकर्ताओं को प्रतिवादी का परिणाम घोषित करने का

निर्देश दिया गया और यदि वह योग्य पाया गया, तो उसे सिविल सेवा परीक्षा मुख्य 2010 से लेने की अनुमति दी जानी चाहिए।_आवेदन की अनुमति देते समय, ट्रिब्यूनल ने अपीलकर्ताओं की ओर से दायर उत्तर पर विचार किया था। अपीलकर्ताओं की ओर से दायर जवाब में कहा गया कि प्रतिवादी की ओर से अपीलकर्ताओं को कोई आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुआ। प्रतिवादी ने विशेष रूप से कहा था कि उसका आवेदन पत्र क्रमांक 37573985 ऊपर नामित कूरियर के माध्यम से 29 जनवरी, 2010 को शाम 4 बजे अपीलकर्ताओं को प्रस्तुत किया गया था। प्रतिवादी ने मुख्य रूप से कूरियर द्वारा उसे इस आशय की दी गई पावती पर भरोसा किया था कि उनका आवेदन पत्र 29 जनवरी, 2010 को शाम 4 बजे अपीलकर्ताओं को सौंप दिया गया था डीटीडीसी, हैदराबाद के क्षेत्रीय कार्यालय के प्रबंधक, प्रशासन, श्री वीएस कुमार राजू द्वारा उक्त कथन के समर्थन में एक हलफनामा भी दायर किया गया था। इस शपथ पत्र के जवाब में अपीलकर्तागण द्वारा भी शपथ पत्र पेश कर प्रतिवादी के पूर्वोक्त कथनों को विशेष रूप से अस्वीकार कर दिया गया था। ट्रिब्यूनल ने उपरोक्त तथ्यों पर विचार किया था और दो संभावनाओं पर भी गौर किया था - या तो प्रतिवादी का आवेदन पत्र अपीलकर्ताओं के कार्यालय में खो गया था या कूरियर एजेंसी ने प्रत्यर्थी के आवेदन पत्र को वितरित करने में विफल रही थी। ट्रिब्यूनल इस अंतिम निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा कि प्रतिवादी

का आवेदन पत्र अपीलकर्ताओं को वास्तव में पत्र प्राप्त हुआ था। हालांकि ट्रिब्यूनल ने अपने आदेश में कहा कि एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचना मुश्किल था कि प्रतिवादी का आवेदन पत्र वास्तव में अपीलकर्ताओं द्वारा प्राप्त किया गया था, ट्रिब्यूनल ने अपीलकर्ताओं को प्रतिवादी का परिणाम घोषित करने का अंतिम निर्देश दिया और यदि वह सिविल सेवा परीक्षा (प्रारंभिक) में सफल पाया गया, उसे सिविल सेवा परीक्षा (मुख्य) देने व साक्षात्कार में बैठने की भी अनुमति दी जानी चाहिए। इस प्रकार, प्रतिवादी द्वारा दायर आवेदन को स्वीकार कर ट्रिब्यूनल ने 1 सितंबर, 2010 के आदेश द्वारा अनुमति दे दी थी।

7. अपीलकर्ताओं द्वारा 2010 की रिट याचिका संख्या 33367 दायर करके ट्रिब्यूनल के पूर्वोक्त आदेश को उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी। संबंधित अधिवक्ताओं को सुनने और उपरोक्त तथ्यों पर विचार करने के बाद, उच्च न्यायालय ने यह कहते हुए याचिका का निपटारा कर दिया कि प्रतिवादी को सिविल सेवा परीक्षा (मेन्स) देने की अनुमति दी जानी चाहिए और यदि वह सिविल सेवा परीक्षा (मेन्स) में योग्य है तो उसे साक्षात्कार में बैठने की भी अनुमति दी जानी चाहिए। उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, याचिका का निपटारा उच्च न्यायालय द्वारा कर दिया गया।

8. यह ध्यान रखना भीउचित है कि उपरोक्त कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान, प्रतिवादी ने सिविल सेवा परीक्षा (मेन्स) दी और मौखिक

साक्षात्कार के लिए भी उपस्थित हुआ। अंतिम परिणाम घोषित नहीं किया गया है और इसे अपीलकर्ताओं द्वारा सीलबंद कवर में रखा गया है। प्रतिवादी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष अंतर्वर्ती आवेदन संख्या 1 दायर किया गया है जिसमें अपीलकर्ताओं को प्रतिवादी का परिणाम घोषित करने और एक विशेष कैडर में एक पद खाली रखने के निर्देश देने की प्रार्थना की गई है ताकि वह सेवा में शामिल हो सके। यह आवेदन भी सुनवाई हेतु लंबित है।

9. अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल श्री पराग पी. त्रिपाठी ने कहा कि ट्रिब्यूनल के आदेश की पुष्टि करने वाला उच्च न्यायालय का आक्षेपित आदेश बिल्कुल अन्यायपूर्ण और अनुचित है, विशेष रूप से इस तथ्य के मद्देनजर कि न तो ट्रिब्यूनल और न ही उच्च न्यायालय न्यायालय किसी अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचा था कि प्रतिवादी का आवेदन पत्र वास्तव में अपीलकर्ताओं को प्रस्तुत किया गया था।

10. विद्वान वकील ने हमें आवेदन पत्रों की स्वीकृति के संबंध में प्रक्रिया से अवगत कराया और उन्होंने इस न्यायालय में सिविल सेवा परीक्षा, 2010 के संबंध में आवेदन पत्रों से संबंधित संपूर्ण प्रासंगिक रिकॉर्ड भी रखा था। उन्होंने हमें बताया कि अपीलकर्ताओं को आवेदन पत्र कैसे प्राप्त होते है। उन्होंने बताया कि अपीलकर्ताओं की सामान्य प्रथा के

अनुसार, जब भी सिविल सेवा परीक्षा से संबंधित कोई भी आवेदन पत्र डाक द्वारा भेजा जाता है, तो आवेदन फार्म के साथ इसे डाक द्वारा भेजने वाले उम्मीदवार को डाक टिकट चिपकाए हुए एक स्व-संबोधित पावती कार्ड संलग्न करना होता है। उक्त पावती कार्ड अपीलकर्ताओं द्वारा संबंधित उम्मीदवार को एक विशिष्ट संख्यात्मक चिह्न चिपकाए जाने के साथ वापस कर दिया जाता है। पावती कार्ड संबंधित उम्मीदवार को डाक द्वारा भेजा जाता है। यदि कोई आवेदन पत्र अपीलकर्ताओं को हाथ से डिलीवरी या कूरियर के माध्यम से प्राप्त होता है, तो जो व्यक्ति एक विशेष काउंटर पर अपीलकर्ताओं के प्रतिनिधि को आवेदन पत्र सौंपता है, उसे एक विशिष्ट मुहर लगाने के बाद एक संख्यात्मक चिह्न के साथ पावती कार्ड दिया जाता है

11. उन्होंने आगे कहा कि अलग-अलग संख्यात्मक चिह्न वाले प्रत्येक स्टाम्प की एक प्रतिकृति को अपीलकर्ताओं द्वारा बनाए गए रजिस्टर में चिपकाकर भी रखा जाता है ताकि पावती चिह्न बनाने के किसी भी प्रयास की स्थिति में धोखाधड़ी का आसानी से पता लगाया जा सके। प्रत्येक दिन प्राप्त आवेदनों से संबंधित ऐसे निशानों और रिकॉर्ड वाले रजिस्टर को इस न्यायालय के समक्ष अवलोकन के लिए रखा गया।

12. अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के अनुसार, उपरोक्त प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए, यदि प्रतिवादी संख्या 37573985 का आवेदन पत्र

अपीलकर्ताओं द्वारा प्राप्त किया गया था, तो एक पावती कार्ड कूरियर के प्रतिनिधि द्वारा प्राप्त किया जाना चाहिए था, जिसने अपीलकर्ताओं के एक प्रतिनिधि को व्यक्तिगत रूप से आवेदन पत्र सौंपा। उन्होंने आगे कहा कि प्रतिवादी के अनुसार, उनका आवेदन पत्र 29 जनवरी, 2010 को शाम 4 बजे प्रस्तुत किया गया था, 29 जनवरी, 2010 को प्राप्त सभी आवेदनों की एक सूची इस न्यायालय को दिखाई गई थी, लेकिन उक्त सूची में, प्रतिवादी के आवेदन पत्र संख्या 37573985 का कोई संदर्भ नहीं था। इसलिए, उन्होंने तर्क दिया कि वास्तव में प्रतिवादी का आवेदन पत्र अपीलकर्ताओं को प्राप्त नहीं हुआ था।

13. अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील ने आगे कहा कि 100 आवेदन पत्र और उनसे संबंधित रिकॉर्ड एक अलग पैकेट में रखे गए हैं और उन्होंने उस प्रणाली को भी समझाया जिसके तहत सभी आवेदन पत्र अपीलकर्ताओं द्वारा प्राप्त और संधा◌ित किए जाते हैं। 29 जनवरी 2010 को प्राप्त आवेदन पत्रों के पैकेट में भी प्रतिवादी का फार्म नहीं मिला।

14. विद्वान वकील ने आगे तर्क दिया कि चूंकि प्रतिवादी का आवेदन पत्र कभी भी अपीलकर्ताओं को प्राप्त नहीं हुआ तो प्रतिवादी का परिणाम घोषित करना उचित नहीं होगा क्योंकि अपीलकर्ताओं के मामले के अनुसार, प्रतिवादी का आवेदन पत्र कभी भी प्राप्त नहीं हुआ था। ऐसी स्थिति में, प्रतिवादी का परिणाम घोषित करना बिल्कुल अन्यायपूर्ण होगा

और एक गलत मिसाल कायम करेगा। इसलिए, उन्होंने कहा कि अपील की अनुमति दी जाए और ट्रिब्यूनल के आदेश की पुष्टि करने वाले उच्च न्यायालय के फैसले को रद्द कर दिया जाए।

15. दूसरी ओर, प्रतिवादी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री एल. नागेश्वर राव ने मुख्य रूप से तर्क दिया कि प्रतिवादी ने डीटीडीसी कूरियर एंड कार्गो लिमिटेड के माध्यम से अपना आवेदन पत्र भेजा था और कूरियर ने अपीलकर्ताओं को फॉर्म वितरित किया था। उन्होंने उपरोक्त नामित कूरियर एजेंसी के एेसे जिम्मेदार अधिकारी द्वारा दायर एक हलफनामे पर भी भरोसा किया, जिसमें कहा गया था कि प्रतिवादी का आवेदन पत्र 29 जनवरी, 2010 को यूपीएससी को दिया गया था।

16. उन्होंने आगे तर्क दिया कि प्रतिवादी के पास आवेदन पत्र जमा करने के संबंध में कोई गलत दावा करने का कोई कारण नहीं था क्योंकि प्रतिवादी परीक्षा के बारे में काफी गंभीर था और वास्तव में उसने सिविल सेवा परीक्षा (प्रारंभिक) उत्तीर्ण की थी और प्रत्यर्थी को सिविल सेवा परीक्षा (मुख्य) और मौखिक साक्षात्कार में भी सफल होने की पूरी उम्मीद थी। उन्होंने आगे कहा कि कूरियर एजेंसी के पास प्रतिवादी का आवेदन पत्र न देने का कोई कारण नहीं था और कूरियर एजेंसी के एेसे जिम्मेदार अधिकारी के पास प्रतिवादी के समर्थन में इस आशय का शपथ पत्र देना के

कुरियर कम्पनी ने आवेदन पत्र अपीलार्थी के यहां जमा करवा दिया यह गलत हलफनामा दाखिल करने का कोई कारण नहीं था।

17. विद्वान वकील ने आगे कहा कि परिणाम घोषित होने से किसी को कोई नुकसान नहीं होगा क्योंकि यदि प्रतिवादी को सफल घोषित नहीं किया जाता है, तो उसे कोई लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन यदि वास्तव में वह परीक्षा में भी सफल पाया जाता है यदि उसे संदेह का लाभ नहीं दिया गया, तो एक प्रतिभाशाली युवा का करियर बर्बाद हो जाएगा। इसलिए, उन्होंने कहा कि ट्रिब्यूनल के आदेश की पुष्टि करने वाला उच्च न्यायालय का निर्णय उचित और कानूनी है और इसलिए, अपील खारिज कर दी जानी चाहिए।

18. हमने विद्वान वकील को विस्तार से सुना है और विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल द्वारा इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रासंगिक रिकॉर्ड का भी सावधानीपूर्वक अध्ययन किया है।

19. यह ध्यान रखना उचित है कि प्रतिवादी ने, किसी भी समय, ट्रिब्यूनल के समक्ष या यहां तक कि इस न्यायालय के समक्ष इस आशय का कोई सबूत पेश नहीं किया था कि अपीलकर्ताओं को प्रतिवादी का आवेदन पत्र क्रमांक 37573985 प्राप्त हुआ था।

20. शुरुआत से ही यानी जिस चरण में ट्रिब्यूनल के समक्ष एक मूल आवेदन दायर किया गया था, प्रतिवादी ने डीटीडीसी कूरियर एंड कार्गो

लिमिटेड के क्षेत्रीय कार्यालय, जिसका शाखा कार्यालय हैदराबाद में है। प्रबंधक प्रशासन द्वारा दायर एक हलफनामे पर भरोसा किया था उनके हलफनामे के अनुसार, प्रतिवादी का आवेदन पत्र 29 जनवरी, 2010 को अपीलकर्ताओं को वितरित किया गया था। आवेदन पत्र उनके द्वारा व्यक्तिगत रूप से वितरित नहीं किया गया था, बल्कि इसे उपरोक्त नामित कूरियर एजेंसी के एक कर्मचारी द्वारा वितरित किया गया था और ताकि उनकी बात को साबित किया जा सके। मान लीजिए, उन्होंने 29 जनवरी, 2010 की डिलीवरी रन शीट संख्या 12878919 पर भरोसा किया था। उक्त रन शीट रिकॉर्ड का एक हिस्सा है। रन शीट का अवलोकन करने पर, हमें अपीलकर्ताओं के किसी भी अधिकारी द्वारा इस आशय की कोई स्वीकृति नहीं मिली कि प्रतिवादी का एक आवेदन पत्र अपीलकर्ताओं द्वारा प्राप्त किया गया था। उक्त रन शीट में उन खेपों की संख्या शामिल है जो यूपीएससी, शाहजहाँ रोड, नई दिल्ली को संबोधित की गई थीं। पांच अलग-अलग खेपों की संख्या और यूपीएससी के नाम के अलावा, जिन्हें खेप भेजी जानी थी, उक्त रन शीट पर कोई संकेत नहीं है कि उक्त खेप यूपीएससी की ओर से प्राप्त की गई थी।

21. हमारी राय में, उपरोक्त रिकॉर्ड के आधार पर, किसी भी तरह से कोई यह नहीं कह सकता कि प्रतिवादी का आवेदन पत्र अपीलकर्ताओं को प्राप्त हो गया था।

22. चूंकि मामला एक युवा व्यक्ति के करियर से जुड़ा है, जो एक अच्छा सिविल सेवक बन सकता है, हमने अपीलकर्ताओं द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड को बहुत सावधानी से देखा था। अपीलकर्ताओं द्वारा अपनाई जा रही प्रणाली को देखने पर, हम पाते हैं कि उक्त प्रणाली बहुत व्यापक और दोषरहित है। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि यदि प्रतिवादी का आवेदन पत्र अपीलकर्ताओं को दिए गए तरीके से प्राप्त हुआ होता, तो इसे कहीं न कहीं दर्ज किया गया होता। यहां तक कि प्रतिवादी के आवेदन पत्र का आठ अंकों का नंबर भी कहीं दर्ज नहीं किया गया है. कूरियर के माध्यम से आवेदन पत्र की प्राप्ति को अपीलकर्ताओं द्वारा 'हाथ से डिलीवरी' माना जाता है। हाथ से आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में, मौके पर ही, एक विशिष्ट संख्यात्मक चिह्न लगा हुआ एक पावती कार्ड उस व्यक्ति को सौंप दिया जाता है जो आवेदन पत्र वितरित करता है। यदि आवेदन पत्र कूरियर एजेंसी के किसी प्रतिनिधि द्वारा अपीलकर्ताओं के कार्यालय में पहुंचाया गया था, तो अपीलकर्ताओं के पास एक अलग संख्यात्मक चिह्न वाला विधिवत मुद्रांकित पावती कार्ड न देने का कोई कारण नहीं था। प्रतिवादी या कूरियर एजेंसी द्वारा ऐसा कोई पावती कार्ड, जिस पर विधिवत मुहर लगी हो, प्रस्तुत नहीं किया जा सका। इस प्रकार, रिकॉर्ड के अवलोकन और मामले के तथ्यों को देखने पर, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि प्रतिवादी

द्वारा कोई सबूत प्रस्तुत नहीं किया जा सका कि आवेदन पत्र अपीलकर्ताओं द्वारा प्राप्त किया गया था।

23. यहां यह ध्यान रखना उचित है कि अंतिम आदेश पारित करते समय, यहां तक कि ट्रिब्यूनल भी निश्चित नहीं था कि प्रतिवादी का आवेदन पत्र अपीलकर्ताओं द्वारा प्राप्त किया गया था या नहीं। ट्रिब्यूनल ने 1 सितंबर, 2010 के अपने अंतिम आदेश के पैरा 8 में निम्नानुसार कहा है:

> "8.....यह बहुत संभव है कि आवेदक का आवेदन गुम हो गया हो। यह भी बहुत संभव है कि कूरियर एजेंसी आवेदक का आवेदन पत्र प्रतिवादी के कार्यालय में पहुंचाने में विफल रही हो।...."।

इस प्रकार, प्रतिवादी को सिविल सेवा परीक्षा देने की अनुमति देने के संबंध में अपीलकर्ताओं को अंतिम निर्देश देते समय भी, ट्रिब्यूनल एक निश्चित निष्कर्ष और विशिष्ट निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा था कि प्रतिवादी का आवेदन पत्र वास्तव में अपीलकर्ताओं द्वारा प्राप्त किया गया था या उनके यहां गुम हो गया।

हमारी राय में, ऐसी परिस्थितियों में, अपीलकर्ताओं को प्रतिवादी को परीक्षा देने की अनुमति देने का निर्देश देना उचित नहीं होगा, खासकर जब

यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं था कि प्रतिवादी ने अपीलकर्ताओं को अपना आवेदन पत्र जमा कर दिया था।

24. हम यह भी नोट करते हैं कि प्रतिवादी की ओर से कुछ लापरवाही हुई थी। अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने हमारा ध्यान यूपीएससी द्वारा दिए गए विज्ञापन की ओर आकर्षित किया था, जिसमें सिविल सेवा में शामिल होने और उस उद्देश्य के लिए परीक्षा देने के इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए गए थे। आवेदन की पावती से संबंधित उक्त विज्ञापन का खंड 7 यहां नीचे दिया गया है:

> "7. आवेदनों की पावती:
>
> किसी उम्मीदवार से आवेदन प्राप्त होने पर तुरंत, आवेदन पत्र के साथ उसके द्वारा जमा किया गया पावती कार्ड उसके आवेदन की प्राप्ति के प्रतीक के रूप में विधिवत मुहर लगाकर आयोग के कार्यालय द्वारा उसे भेज दिया जाएगा। यदि किसी उम्मीदवार को 30 दिनों के भीतर पावती कार्ड प्राप्त नहीं होता है, तो उसे तुरंत अपना आवेदन पत्र संख्या (8 अंक) और नाम और परीक्षा का वर्ष बताकर आयोग से संपर्क करना चाहिए। आयोग के काउंटर पर व्यक्तिगत रूप से आवेदन पत्र पहुंचाने वाले उम्मीदवारों को काउंटर पर ही पावती कार्ड जारी किया जाएगा। केवल यह तथ्य कि किसी

उम्मीदवार का आवेदन आयोग द्वारा स्वीकार कर लिया गया है, इसका मतलबके आवेदन की अस्वीकृति के बारे में यथाशीघ्र सूचित किया जाएगा। यह नहीं है कि परीक्षा के लिए उसकी उम्मीदवारी आयोग द्वारा स्वीकार कर ली गई है। उम्मीदवारों को परीक्षा में उनके प्रवेश या उन"

25. प्रतिवादी के अनुसार, उसने अपना आवेदन पत्र 28 जनवरी, 2010 को उपरोक्त कूरियर के माध्यम से अग्रेषित किया था। यदि प्रतिवादी को उस तारीख से 30 दिनों की अवधि के लिए कोई पावती नहीं मिली, जिस दिन उसने अपना आवेदन पत्र अग्रेषित किया था, तो उसे अपीलकर्ताओं के कार्यालय में आवश्यक पूछताछ करनी चाहिए थी। यहां तक कि प्रतिवादी के मामले के अनुसार, 20 अप्रैल, 2010 को पहली बार उसने अपने आवेदन पत्र के बारे में पूछताछ की कि उसे अपीलकर्ताओं से पावती कार्ड नहीं मिला था। जैसा कि पूर्वोक्त खंड संख्या 7 में कहा गया है, एक विवेकपूर्ण उम्मीदवार के रूप में, प्रतिवादी को फरवरी, 2010 के अंत तक पूछताछ करनी चाहिए थी, लेकिन प्रतिवादी को सबसे अच्छी तरह ज्ञात कारणों से, उसने पूछताछ करने के लिए 20 अप्रैल, 2010 तक इंतजार किया। इस बात की जांच की जाएगी कि क्या उनका आवेदन पत्र विरोधियों को प्राप्त हुआ था। हमारी राय में, राज्य का एक जिम्मेदार अधिकारी बनने का इच्छुक कोई भी जागरूक छात्र इतना उदासीन नहीं

रहेगा कि दो महीने से अधिक समय तक कोई पूछताछ न करे। यह भी ध्यान देने योग्य है कि प्रतिवादी पहली बार परीक्षा नहीं दे रहा था। उनके मुताबिक, उसने पहले भी परीक्षा दी थी लेकिन दुर्भाग्य से वह सफल नहीं हो पाया। इस प्रकार, उसे इस बात का अनुभव था कि आवेदन पत्र कैसे भरा जाता है, उसे कैसे जमा किया जाना है और अपीलकर्ताओं द्वारा पावती कार्ड कैसे भेजा जाता है। हमारी राय में, इस लापरवाही के कारण उसे यह कष्ट झेलना पड़ा और इस घटना के लिये केवल वह ही दोषी है।

26. उपरोक्त कारणों से, हमारा विचार है कि अपीलकर्ताओं को प्रतिवादी के अंतिम परिणाम घोषित करने के लिए निर्देशित नहीं किया जा सकता है, खासकर जब उसका आवेदन पत्र निर्धारित अवधि के भीतर अपीलकर्ताओं द्वारा प्राप्त नहीं हुआ था। हम दूसरे आवेदन पत्र को नजरअंदाज करते हैं जो ट्रिब्यूनल द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसरण में उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। हम यहां कह।सकते हैं कि इस न्यायालय ने बार-बार देखा है कि एक अंतरिम आदेश ऐसी प्रकृति का नहीं होना चाहिए जिसके आधार पर, जैसा भी मामला हो, किसी याचिका या आवेदन को अंततः अनुमति दी जाए या दी जाए। अंतरिम चरण हम दोहराते हैं कि आम तौर पर बातचीत के चरण में ऐसी कोई राहत नहीं दी जानी चाहिए जिसके आधार पर अंतिम राहत, जो मांगी गई है और मामले के निपटारे के लिए उपलब्ध है, दी जाती है। हालाँकि, हमने पाया है कि

अक्सर अदालतें छात्रों के प्रति अधिक सहानुभूति रखती हैं और अंतरिम आदेशों द्वारा अधिकारियों को निर्देश दिया जाता है कि वे छात्रों को यह सुनिश्चित किए बिना परीक्षा देने की अनुमति दें कि संबंधित उम्मीदवार को परीक्षा देने का अधिकार है या नहीं। किसी असाधारण मामले में किसी विशेष कारण से, यदि ऐसा निर्देश दिया जाता है, तो अदालत को परिणाम घोषित होने से पहले मामले को गुण-दोष के आधार पर अंतिम रूप से निपटाना चाहिए। मौजूदा मामले में, हमने पाया है कि प्रतिवादी ने न केवल प्रारंभिक परीक्षा दी, बल्कि मुख्य परीक्षा भी दी और अंतरिम आदेशों के आधार पर साक्षात्कार के लिए भी उपस्थित हुआ, हालांकि उसे किसी भी परीक्षा में बैठने का कोई अधिकार नहीं था। हमारी राय में, ऐसे अंतरिम आदेश देने से बचना चाहिए क्योंकि वे न केवल परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था का काम बढ़ाते हैं बल्कि अदालत का दरवाजा खटखटाने वाले उम्मीदवारों को झूठी आशा भी देते हैं।

28. यहां ऊपर बताए गए कारणों से, हम उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले के साथ-साथ ट्रिब्यूनल के आदेश को रद्द करके और खर्चा के बारे में कोई आदेश दिए बिना यह अपील अस्वीकार करते हैं। प्रतिवादी द्वारा दायर अंतर्वर्ती आवेदन भी खारिज कर दिया गया है।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल ''सुवास'' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी श्री मदन गोपाल आर्य, (आर.जे. एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरणः यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिये स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उददेश्य के लिये इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उददेश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उददेश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।